International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 05, May 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

नवउदारवाद के चालीस वर्ष: बुद्धिजीवी एवं नीति निर्माताओं के लिए सबक

डॉ.रमेश चंद बैरवा
सह आचार्य,राजनीति विज्ञानराजनीति विज्ञान
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर

1980 से दुनिया में एवं 1990 से भारत में प्रचलन में आई,शिक्षा,मीडिया एवं राजनैतिक जगत में बेहद चर्चित तथा आमजन पर जबरन थोपी गई नवउदारवाद (Neoliberalism) की विचारधारा एवं नीतियां असल में (पूंजीवादी) उदारवाद का तृतीय चरण है।साधारण शब्दों में उदारवाद को अंग्रेजी भाषा में Liberalism कहते हैं, जिसकी व्युत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द Los Liberales से हुई है,जिसका अर्थ है-स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित। वैसे तो Liberal शब्द का प्रयोग यूरोप में 16वीं सदी से सामंती राजसत्ता के जुल्म एवं ज्यादती तथा धार्मिक कट्टरता एवं कर्मकांड के खिलाफ होता रहा,फिर भी Liberalism शब्द का पूर्ण रूप से प्रयोग प्रथम बार वर्ष 1815 में स्पेन में हुआ,जब लोगों ने राजशाही के स्थान पर संविधान के शासन की मांग उठाई।

Hobbes के 'Leviathan' (अर्थात निरंकुश शासन) के स्थान पर John Locke ने सीमित सरकार (Limited Government) का पक्ष लिया... 'Two Treatise on Civill Government' नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक-John Locke नागरिकों के लिए जीवन,स्वतंत्रता और संपत्ति (Life,Liberty and Property-LLP) के natural rights सहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करते हैं और शासक (Ruler) के लिए शासितों की सहमति (Consent of the Governed अर्थात नागरिकों की सहमति) को जरूरी मानते हैं। इसीलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है।

लॉक ने लिखा है कि "किसी को भी दूसरे के स्वास्थ्य,
स्वतंत्रता या संपत्ति को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए।"

John Locke समर्थित प्राकृतिक अधिकारों को ही कुछ मामूली से संशोधन के साथ 4 जुलाई 1776 की अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा में अमर वाक्य के रूप में इस प्रकार उल्लेखित किया है:

"हम इन सिद्धांतों को स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उन्हें अपने स्रष्टा द्वारा कुछ अविच्छिन्न अधिकार मिले हैं। जीवन,स्वतंत्रता और सुख की खोज (Right to Life, Liberty and Persuit of Happiness) इन्हीं अधिकारों में है। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए समाज में सरकारों की स्थापना हुई जिन्होंने अपनी न्यायोचित सत्ता शासित की सहमति से ग्रहण की। जब कभी कोई सरकार इन उद्देश्यों पर कुठाराघात करती है तो जनता को यह अधिकार है कि वह उसे बदल दे या उसे समाप्त कर नई सरकार स्थापित करे।"....

American Declaration of Independence (4 July 1776) says that- "We hold these truths to be self-evident,that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

--That to secure these rights, Governments are instituted among Men,deriving their just powers from the consent of the governed,

--That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government"...

प्राकृतिक अधिकारों के इसी सिद्धान्त को 1789 की French Revolution के 'Declaration of Rights of Man and of the Citizen' ने यह घोषित कर और भी संपुष्ट किया कि अपने अधिकारों के संबंध में मनुष्य स्वतंत्र तथा समान पैदा होता है,समान अधिकार रखता है...(Men are born and remain free and equal in rights.Social distinctions can be founded only on the common good (Art.1)...The goal of any political association is the conservation of the natural and imprescriptible rights of man.These rights are liberty, property, safety and resistance against oppression."

आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने गए ब्रिटिश अर्थशास्त्री Adam Smith ने 1776 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध कृति-'An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations' के जरिये उदारवाद को आर्थिक आधार प्रदान किया। ज्यां जेक्स रूसो,जे एस मिल,टी एच ग्रीन,जेरेमी बेंथम, डेविड रिकार्डो,थॉमस माल्थस के विचारों के प्रभाव में 19वीं शताब्दी में उदारवाद का अभूतपूर्व विकास हुआ।

20वीं सदी में Fabian Society, British Labour Party, Harold J Laski, G D H Cole,Arnest Barker,J M Keynes जैसे खास चिंतकों के नाम है जिन्होंने उदारवाद का समर्थन एवं पोषण किया है।

उदारवाद आधुनिक पूंजीवादी युग की प्रधान एवं प्रभुत्वशाली धारणा है,विचारधारा है। यह भी गौरतलब है कि उदारवाद पढ़ने एवं सुनने में बहुत कर्णप्रिय एवं आकर्षक शब्दावली लगती है। प्रथम दृष्टया उदारवाद के बारे में सुनकर ही ऐसा लगता है मानों कि यह स्वतंत्रता,समानता, सहनशीलता,भाईचारा, लोकतंत्र और जनकल्याण जैसे मानव मूल्यों की पोषक विचारधारा है। लेकिन हकीकत में ऐसी नहीं है। मजबूरी में हो सकता है यह जनकल्याणकारी दिखने का दिखावा करती हो,लेकिन हकीकत में इसका मूल चरित्र 'मुंह में राम,बगल में छुरी'जैसा दोगला ही है। कथनी-करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जनकल्याणकारी होने का चाहे कितना ही दावा या दिखावा करे,उदारवाद अंततः -येनकेन प्रकारेण अधिक से अधिक आर्थिक मुनाफा कमाने को अपना धर्म समझने वाले-पूंजीपति वर्ग की ही राजनीतिक विचारधारा है। इसमें समय-समय पर संशोधन पूंजीपति वर्ग की वर्गीय जरूरतों के हिसाब से होता रहा है। पूंजीवाद के बदलते स्वरूप एवं वर्गीय जरूरतों के मुताबिक उदारवाद को बाजारू उत्पाद की भांति आकर्षक बनाये रखने के लिए बौद्धिक चोला भी पहनाया जाता रहा है। इसी तर्ज एवं तर्क पर उदारवाद को पूंजीवाद की नई वर्गीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 1980 के बाद से नवउदारवाद की आकर्षक शब्दावली के रूप में पेश किया है,जो कि आमजन की दृष्टि से एक और धोखा ही साबित हुई है।

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया हुआ है कि 1980 से शुरू हुआ नवउदारवाद,उदारवाद का तृतीय चरण है। प्रथम चरण द्वितीय विश्व युद्ध या खासकर 1929 की मंदी तक माना गया है,जिसे नकारात्मक उदारवाद (Negative Liberalism) कहा गया। नकारात्मक उदारवाद आर्थिक प्रगति एवं मानव कल्याण के लिए Adam Smith के व्यक्ति के आर्थिक मामलों में राज्य के अहस्तक्षेप 'Laissez faire' एवं 'Invisible Hand of Market' के जरिये राज्य (अर्थात सरकार) से Free Market-Free Trade की नीति पर चलने के लिए जोर देते हैं। नकारात्मक उदारवाद का दार्शनिक आधार व्यक्तिवाद है। यह नागरिकों के लिए जीवन,स्वतंत्रता एवं संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक है। नकारात्मक उदारवाद,राज्य (या यूं कहें कि सरकार) को एक आवश्यक बुराई मानता है। इसकी नजर में वही सरकार सबसे अच्छी है,जो कम से कम शासन करे,अर्थात Minimum Government... नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति के हित में ही समाज का हित मानता है,अर्थात व्यक्ति को ही सर्वोपरि मानता है,समाज को नहीं।

चूंकि उदारवाद पूंजीवाद की राजनैतिक विचारधारा है। और पूंजीवाद की खासियत यह है कि यह व्यवस्था ना तो शोषण विहीन हो सकती है और ना ही संकटविहीन। पूंजीवाद की उत्पादन प्रणाली में पूंजी का गिने चुने हाथों में केन्द्रीयकरण एवं संचय तथा मेहनतकश वर्ग का उत्तरोतर दरिद्रीकरण हो जाने से आमजन के पास पैसे की कमी आ जाती है। क्रयशक्ति कमजोर हो जाती है। बाजार में ग्राहकों की भारी कमी हो जाती है। इससे अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति (demand and supply) का चक्र बुरी तरह गड़बड़ा जाता है। लेकिन यह संकट भीषण व विकराल रूप भी ले लेता है और ऐसा ही 1929 में भी हुआ। अमेरिका,ब्रिटेन जैसे विकसित पूंजीवादी देशों तक को 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने बुरी तरह भीषण संकट में ला दिया। पूंजीवादी देशों की सरकारों ने 1930 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बीच तक मंदी से निजात पाने के लिए अनेक प्रयास किये। विश्वयुद्ध के दौरान रक्षा क्षेत्र में जमकर सरकारी पैसा झोंक कर बाजार में मांग बढ़ाने के भी प्रयास किये। लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं रहे। इधर पूंजीवाद के ही सबसे पतनशील स्वरूप (most decadent form-या यूं कहें पूंजीवाद की ही कोख से निकले-Hitler व मुसोलिनी के फासीवाद (Fascism) ने पूंजीवादी लोकतंत्र के उदारवादी चहरे को बेनकाब कर दिया। पूंजीवादी देशों का आर्थिक संकट इतना विकराल था कि इसने Adam Smith के free market-free trade के Laissez-Faire वाले पूंजीवाद की काबिलियत एवं वैधता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया। उदारवादी (पूंजीवादी) चिंतक व बुद्धिजीवी बेहद परेशान थे। इसी दौरान रूस सहित सोवियत संघ के अन्य देशों में सरकारी योजना के तरीके से आर्थिक विकास तेजी से हो रहा था। पूंजीवादी संकट के हल के लिए हिटलरी नुस्खा भी कारगर साबित नहीं हो पा रहा था। बल्कि फासीवाद ने तो मानवता एवं लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया। Hitler vs Rest की स्थिति कर दी थी। पूंजीवाद के इस चौतरफा संकट का हल अंततः अब Adam Smith के Laissez Faire या Free Market से नहीं,बल्कि John Meynard Keynes के 'Social Market' अर्थात State Intervention के जरिये किया जाना तय हुआ। इस नीति को पूंजी और श्रम के मध्य एक महान समझौता 'Great Compromise' का नाम भी दिया गया। इसी से पूंजीवाद में लोककल्याणकारी राज्य की सैद्धांतिक अवधारणा का सूत्रपात हुआ,जिसे राजनीति विज्ञान की शब्दावली में सकारात्मक उदारवाद (Positive Liberalism) की संज्ञा दी गई। इसे ही उदारवाद का द्वितीय चरण माना गया है।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति Franklin Delano Roosevelt ने इस संकट से निजात दिलाने के लिए 'New Deal' का लोककल्याणकारी कार्यक्रम अपनाया। Capitalist State Intervention को विस्तार से जानने के लिए Keynes की महत्वपूर्ण कृति 'The General Theory of Employment, Interest and Money' खास पुस्तक है। लेकिन कींस या रूजवेल्ट को समाजवादी मानना बड़ी भूल होगी। ये तो सिर्फ Laissez-Faire के खिलाफ मजबूरी में थे। असल में तो ये पूंजीवाद के ही पक्षधर थे। इन्होंने अपने समय की आंतरिक एवं बाहरी हालातों का जायजा लेकर पूंजीपति वर्ग की सहमति से ही पूंजीवाद को संकट से बचाने के अन्य उपाय बुरी तरह विफल होते देख मजबूरी में लोककल्याणकारी राज्य का नुस्खा बताया था। असल में लोककल्याणकारी राज्य या सकारात्मक उदारवाद को अपनाना पूंजीवाद के लिए एक किस्म का 'रक्षा कवच' (Safety Valve) था।

पूंजीपति वर्ग द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उदारवाद के लोककल्याणकारी स्वरूप को अपनाए जाने के पीछे मूल वजह मानवीयता नहीं,असल में तो पूंजीपति वर्ग की वर्गीय मजबूरी ही थी। रूजवेल्ट जो द्वितीय विश्व युद्ध तक अमेरिकी राष्ट्रपति थे ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान 'New Deal' लागू किये जाने की असली वजह अपनी ही जुबान में कुछ ऐसे बताई...

"It is my administration which has saved the system of private profit and free enterprise"-(F D Roosevelt

अर्थात पूंजीवाद को ही बचाने के लिए New Deal जैसा कार्यक्रम लागू किया है। पूंजीपति वर्ग द्वारा लोककल्याणकारी राज्य (सकारात्मक उदारवाद) की नीति अपनाई जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

1. 1929 की विश्वव्यापी भीषण आर्थिक मंदी,जिसने दुनिया को ठीक से यह बता दिया कि पूंजीवाद सिर्फ शोषणमूलक ही नहीं,अपितु एक संकटमूलक व्यवस्था भी है। पूंजीवाद ने ही हिटलर जैसे पूंजीवादी तानाशाह को पैदा कर दिया। जिसने दुनिया में शांति एवं लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है।
2. अमेरिका,ब्रिटेन,फ्रांस जैसे पूंजीवादी देशों तक में मजदूर आंदोलन का मजबूत होना।
3. भारत सहित एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के सैंकड़ों देशों में साम्रज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ तेज होते आज़ादी के आंदोलन,और इन सबसे बढ़कर;
4. 1917 की रूस की समाजवादी सर्वहारा क्रांति के बाद दुनिया में Communism की विचारधारा के तेजी से बढ़ते विश्वव्यापी असर का पूंजीवाद पर बढ़ता दबाब।

उल्लेख है कि जर्मनी के आमजन को राष्ट्रवाद व देशभक्ति के नाम की overdoze देकर करोड़ों लोगों की मौत के जिम्मेदार तथा दुनिया को जीतने का सपना देखने वाले Hitler ने रूसी लाल सेना के हमले से डरकर 30 अप्रेल 1945 को खुद ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसके कुछ दिन बाद ही विश्वयुद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ज्यादातर पूंजीवादी एवं भारत जैसे नवोदित देशों में सकारात्मक उदारवाद के लोककल्याणकारी राज्य के स्वरूप को अपनाया गया।कुछ विद्वानों ने इसे Capitalism और Socialism का मिश्रण बताया। भारत के संविधान के मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य के लोककल्याणकारी स्वरूप का बेहतरीन उल्लेख मिलता है। लोककल्याणकारी राज्य के जरिये प्रचलित सकारात्मक उदारवाद की विचारधारा 1945 से 1970 के कुछ वर्षों तक चले 'Golden Phase of Capitaism' में बड़ी लोकप्रिय रही। ठीक-ठाक चली। लेकिन 1973 के तेल संकट,वियतनाम के खिलाफ युद्ध में अमेरिका बजट व्यय में तेजी से बढ़ोतरी के कारण अमेरिका में आर्थिक संकट बढ़ गया। इसी दौरान पूंजीवादी देशों में मजदूर आंदोलन कमजोर पड़ने लगा तथा अमेरिका के साथ शीतयुद्ध में सोवियत संघ के arms race में आ जाने के कारण सोवियत अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई। इससे पूंजीवाद पर Communism की विचारधारा का दबाब कम होने लगा। इन्हीं हालातों का फायदा उठाकर पूंजीवादी देशों खासकर USA एवं UK में पूंजीपति वर्ग कीन्सवाद को त्यागकर खुलेरूप से पूंजीपति परस्त नवउदारवाद की नीतियों को अपनाने का दबाब डालने लगा।

'Capitalism and Freedom' नामक कृति के लेखक Milton Friedman एवं 'The Constitution of Liberty' तथा 'The Road to Serfdom' के लेखक Friedrich won Hayek जैसे बाजार संचालित अर्थव्यवस्था के समर्थक अर्थशास्त्रियों एवं बुद्धिजीवियों के बताए रास्ते पर पूंजीवाद के 'सकारात्मक' या लोककल्याणकारी स्वरूप को खत्म करने के नीतिगत प्रयास 1980 से ही USA एवं UK में शुरू हो गए।

'Public is Bad
Private is Good' का विचार रखना एवं लोककल्याण की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़,पूरी बेशर्मी से चहेते पूंजीपति/कॉरपोरेट के हित में Crony Capitalism की नीतियों की पोषक-

नवउदारवाद (Neoliberalism) की नीतियों की शुरुआत UK में तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरिट थैचर एवं USA में रोनाल्ड रीगन ने की।

संक्षेप कहें तो घोर व्यक्तिवाद का समर्थक होने के कारण नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप (State Intervention) के खिलाफ है। पुलिस राज्य का समर्थक है। इसके विपरीत सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में है।

यहाँ नकारात्मक उदारवाद एवं नवउदारवाद के मध्य मूल अंतर को समझना अत्यंत जरूरी है। जहां Adam Smith का नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में हर स्तर पर हर किस्म के राज्य हस्तक्षेप के खिलाफ है,वहीं नवउदारवाद लोककल्याण के लिए (जैसे अमीरों पर कर) व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का तो विरोध करता है। नवउदारवाद, सकारात्मक उदारवाद में Common Man के कल्याण के लिए किये गए सरकारी हस्तक्षेप की वापसी की बात करता है। लेकिन साथ में गौर करने वाली बात यह है कि नवउदारवाद असल में Corporates/ Capitalist को उद्योग एवं व्यापार के लिए समुचित सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए State Intervention के पूरी तरह पक्ष में है। अर्थात नवउदारवाद का पुरजोर मानना है कि सकारात्मक उदारवाद के दौर में Public Welfare के लिए सरकार द्वारा किये हुए हस्तक्षेप को सरकार वापस ले और पूँजीपतियों के हित में सरकार हस्तक्षेप करे। अर्थात यह Adam Smith वाला पूर्ण Lasseiz-Faire नहीं है। नवउदारवाद राज्य के हस्तक्षेप का समर्थक तो है लेकिन पूंजीपति के हित में।

1980 से लागू हुई नवउदारवाद की इस विचारधारा को दुनिया में 40 वर्ष हो गए हैं तथा India में July 1990 से लागू किये जाने के बाद 20 वर्ष होने को हैं। नवउदारवाद की विचारधारा ने ही उदारीकरण,निजीकरण एवं वैश्वीकरण (Liberalization, Privatization and Globalization-LPG) की नीतियों को बढ़ाया है,जिसे विश्व प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक Karl Polani ने एक 'महापरिवर्तन'(Great Transformation) की संज्ञा दी है। नवउदारवाद की इन पूंजीपति परस्त LPG की नीतियों के जरिये सरकारें उच्च आर्थिक वृद्धि दर के माध्यम से आमजन की जिंदगी में आर्थिक खुशहाली लाने,शांति,न्याय एवं लोकतंत्र की मजबूती का दावा करती रही है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा हो पाया?

पिछले 40 वर्ष का अनुभव तो यही बताता है कि नवउदारवाद के दौर में सरकार का लोककल्याणकारी स्वरूप बुरी तरह कमजोर कर दिया गया है। सरकारें अब खुलेतौर पर आमआदमी विरोधी तथा ख़ास आदमी अर्थात पूंजीपति परस्त नीतियां लागू करने पर आमादा हैं। अब तो स्थिति यह है कि नवउदारवाद ने ही मुक्त बाजार-मुक्त व्यापार के पूंजीवादी मूल्यों की सरासर अनदेखी कर अपने चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुचाने की नीयत से Crony Capitalism को भी पनपाया है। इसलिए आजकल सरकार को पूँजीपतियों की सरकार से ज्यादा पब्लिक में ही अम्बानी अडानी की सरकार बोला जाता है। नवउदारवाद के इस दौर में भारत सहित अनेक देशों में आर्थिक वृद्धि दर तो निश्चित रूप से बढ़ी है लेकिन यह असमान एवं असंतुलित रही है। सरकारी क्षेत्र का निजीकरण किया है। नवउदारवाद के कारण आर्थिक विषमता, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार बढ़ा है। अन्याय,अपराध एवं अनाचार बढ़ा है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य महंगा हुआ है। लोकतंत्र कमजोर हुआ है। शांति एवं सद्भाव भी बिगड़ा है। पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है।

MNCs की हर हाल में मुनाफा कमाने की लत के कारण एवं धनाढ्य तबके द्वारा अनाप-शनाप उपभोग बढ़ाने के कारण उच्च तकनीकी व प्रौद्योगिकी का प्रकृति के बेरहमी से भी दोहन के लिए उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरण का तेजी से छरण हुआ है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन की चुनौती आज बड़ी चिंता का विषय है।

विश्व आर्थिक मंच पर प्रसिद्ध संस्था ऑक्सफैम द्वारा प्रस्तुत 2019 की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के सिर्फ 2153 सबसे धनाढ्य व्यक्ति विश्व की 60 प्रतिशत दौलत के मालिक बन बैठे हैं। भारत के सिर्फ एक प्रतिशत सबसे धनाढ्य अकेले ही 77 फीसद दौलत के मालिक बन गए हैं। जेंडर आधारित असमानता का भी आलम यह है कि दुनिया के सिर्फ 22 सबसे धनी पुरुष अकेले ही दुनिया की तमाम महिलाओं के पास उपलब्ध दौलत के बराबर दौलत रखते हैं। वेतन तक से आय की स्थिति में भी गैरबराबरी इतनी विकराल है कि एक ग्रामीण मजदूर को एक गारमेंट कम्पनी के एक्जीक्यूटिव को मिलने वाले वेतन के बराबर वेतन पाने में 941 वर्ष लग जाएंगे।

भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था तो जरूर हो गई है लेकिन मानव विकास सूचकांक 2019 की 189 देशों की सूची में भारत का स्थान 129वां है,जो कि हमारी बदतर स्थिति को बताता है।

Covid 19 के प्रकोप ने तो आमजन की हालात और भी बदतर कर दिए हैं। मजदूर बेहाल है। रोजगार नहीं है। भूखों मरने लगे हैं। काम के घण्टे 8 से बढाकर 12 घण्टे कर दिए हैं। छोटे उद्योग धंधे बुरी तरह पिट गए हैं। किसान एवं मध्यम वर्ग के हालात भी अब बिगड़ेंगे ही। आर्थिक मंदी और कोरोना की महामारी तक के इस बुरे दौर में भी नीतियां कॉरपोरेट के खास हित को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है।

जाति एवं जेंडर के नाम भी सामाजिक उत्पीडन भी बढ़ा है। जाति व धर्म के नाम नफरत व हिंसा बढ़ने के लिए अनुकूल हालात बने हैं। नवउदारवाद की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उपजे जन असन्तोष से निपटने के लिए 'फूट डालो और राज करो' (Divide and Rule) की तरकीब अपनाई हुई है। कोरोना का भी साम्प्रदायिकरण करने के प्रयास हुए हैं।

असल में नवउदारवाद ने स्वतंत्रता,समानता,सद्भाव, शांति,लोकतंत्र,न्याय सहित समाजवाद एवं सेक्युलरिज़्म के हमारे संविधान सम्मत मूल्यों को कमजोर किया है। इसलिए नवउदारवाद के 40 वर्ष के कड़वे अनुभव से सच्चे सबक लेकर बुद्दिजीवी वर्ग एवं नीति निर्माताओं की आज खास जिम्मेदारी है कि 'We, the People' के हित में इस विषमतामूलक एवं विभाजनकारी नवउदारवाद की विचारधारा का परित्याग करे तथा संविधान सम्मत आमजन हितैषी नीतियां अपनाएं।

क्योंकि...

अंधेरा अब तो और घना है,इसलिए,हम तो कहेंगे...

ये वक्त की आवाज है,

मिलके चलो,मिलके चलो।

दोस्तों,दिया बत्ती से ज्यादा जरूरी है,हम अपने दिमाग की बत्ती जरूर जलाएं और

यह कार्य बुद्दिजीवी वर्ग ठीक से कर सकता है।

संदर्भ सूची

1.Harold J. Laski,A Grammar of Politics

2. American Declaration of Independence,4 July 1776

3. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,1776

4. John Meynard Keynes, General Theory of Employment, Interest and Money: with The Economic Consequences of the Peace,

5.Milton Friedman, Capitalism and Freedom,1962

6.Oxfam International Report 2019,Together, For a More Equal World